

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

अपीलीय सिविल

गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति के समक्ष

मैसर्स भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, बीएच आईडब्ल्यू एएन आई, अपीलकर्ता।

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम,आदि,-प्रतिवादी।

1970 के आदेश क्रमांक 167 से प्रथम अपील।

मई 25, 1971.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948 का XXXIV) - धारा 51 और 82 (2)  
- विकलांगता लाभ का भुगतान - नियोक्ता का दायित्व - क्या कर्मचारी की  
कामकाजी या कमाई क्षमता को प्रभावित करने वाली विकलांगता पर निर्भर है -  
तथ्य की खोज ट्रायल कोर्ट द्वारा अपील - चाहे धारा 82 (2) के तहत उच्च न्यायालय  
में हो।

501

अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा  
51 के प्रावधान, जो नियोक्ता-प्रबंधन को उत्तरदायी बनाते हैं, अनिवार्य हैं। दायित्व  
केवल इसलिए बनता है क्योंकि विकलांगता हुई है और यह विचार करना कि क्या  
उस विकलांगता ने कर्मचारी की कामकाजी या कमाई क्षमता को प्रभावित किया

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

है, महत्वहीन हो जाता है। अधिनियम या किसी विनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दर्शाता हो कि यदि किसी कर्मचारी की काम करने या कमाने की क्षमता, जो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और विकलांग हो गया है, तो प्रबंधन का दायित्व उस सीमा के अधीन होगा, जिस सीमा तक उसका काम करने या कमाने की क्षमता खराब हो गई है। अधिनियम की धारा 51 के तहत, नियोक्ता का प्रबंधन विकलांगता लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही उस विकलांगता के परिणामस्वरूप घायल कर्मचारी की कामकाजी या कमाई क्षमता का नुकसान हुआ हो। (पैरा 7 और 8)।

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 82(2) के आधार पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाला गया तथ्य अंतिम है। इस धारा के अनुसार, यदि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है तो उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। (पैरा 10)

श्री एस. पी. एम. मित्तल, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, भिवानी के न्यायालय के दिनांक 30 जुलाई, 1970 के आदेश से पहली अपील, जिसमें उत्तरदाताओं के खिलाफ रुपये के भुगतान का डिक्री पारित किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा आवेदक को 2,553.72 पैसे दिए गए और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

जी सी गर्ग. अधिवक्ता, अपीलकर्ता को।

उत्तरदाताओं के लिए के एल के कपूर, एक वकील।

निर्णय

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति.—(1) यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम और इसके प्रबंधक श्री गणपत राय मंगला के खिलाफ मेसर्स भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी द्वारा एक अपील है। यह श्री एस.पी.मित्तल, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, भिवानी के 30 जुलाई, 1970 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

(2) अपील के तथ्य इस प्रकार हैं: -

(3) मुंशी राम अपीलकर्ता की कंपनी में रीलर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 31 मई, 1965 को सुबह 10.30 काम करना शुरू किया। कुछ समय तक काम करने के बाद, वह उस तरफ चले गए जहां बंडल प्रेस रील वाले धागे को डंप करने का काम कर रहा था। उसका पैर फिसल गया और उसका दाहिना हाथ चलती बेल्ट और पुली में फंस गया और उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली कट गई।

502

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1973)2

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 75(2)(सी) के तहत एक आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ किया गया था, खाते पर दावा करते हुए मुंशी राम की छोटी उंगली के क्षत-विक्षत होने पर रु. 2,553.72, इस आधार पर कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप मुंशी राम की छोटी उंगली क्षतिग्रस्त हो गई, अपीलकर्ता की ओर से प्रेस के चारों ओर बाड़ लगाने और बेल्ट को स्थानांतरित करने वाली जगह प्रदान न करने की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई। यह दलील दी गई कि निगम रुपये का दावा करने का हकदार था। 243.72 अस्थायी विकलांगता के कारण और शेष कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के कारण। अपने

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

लिखित बयान में, उत्तरदाताओं ने उपरोक्त आरोपों का खंडन किया और इस बात से इनकार किया कि आवेदक किसी भी मुआवज़ायामूर्ति का हकदार था।

(5) पार्टियों के बीच दलीलों ने निम्नलिखित मुद्दों को जन्म दिया: - "

(1) क्या भिवानी टेक्सटाइल मिल्स न्यायिक व्यक्ति नहीं है, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या है?

(2) क्या पार्टियों के बीच गलत संबंध के लिए आवेदन कानून की नजर में गलत है?

(3) क्या आवेदक आवधिक भुगतान के वास्तविक वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त अस्थायी विकलांगता का दावा कर सकता है?

(4) क्या इस न्यायालय के पास दावे के अनुसार ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है?

(5) क्या दुर्घटना के दिन मुंशीराम की उम्र 27 वर्ष थी, यदि नहीं, तो दुर्घटना के समय क्या उम्र थी?

(6) क्या उत्तरदाताओं की ओर से कोई लापरवाही हुई?

(7) क्या जैसा कि आरोप लगाया गया है, दुर्घटना बंडल प्रेस मशीन की चलती बेल्ट के कारण हुई थी?

(8) क्या दुर्घटना के दिन मशीन बंद थी, यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा?

503

(9) क्या फ़ैक्टरी अधिनियम की धारा 21 का कोई उल्लंघन हुआ था?

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

(10) क्या नियोक्ता ने फैक्ट्री अधिनियम के तहत नियमों के पालन के लिए उचित सावधानी बरती है?

(11) कर्मकार को देय सही राशि क्या है?

(6) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री जी.सी. गर्ग ने मुख्य रूप से मुद्दे संख्या 3 और 6 के तहत तर्क दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चोट लगने के बाद भी, उस अवधि को छोड़कर, जिसके लिए उनका इलाज चल रहा था। वह अपीलकर्ता के साथ अद्वितीय क्षमता के साथ काम कर रहा है और उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली के नुकसान के परिणामस्वरूप न तो उसकी कार्य क्षमता और न ही उसकी कमाई की क्षमता किसी भी तरह से प्रभावित हुई है और इस प्रकार, विकलांगता लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है। कर्मचारी की स्थायी विकलांगता का आधार. अधिनियम की धारा 51 के तहत विकलांगता लाभ का दावा किया गया है। वह अनुभाग इस प्रकार है: -

51. (1) इस अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों, यदि कोई हो, के अधीन, विकलांगता लाभ देय होगा-

(ए) ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसी विकलांगता की अवधि के दौरान अस्थायी विकलांगता का सामना करता है;

(बी) ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन के दौरान स्थायी आंशिक विकलांगता का सामना करता है;

(सी) ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन के दौरान स्थायी पूर्ण विकलांगता का सामना करता है; और

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

(डी) किसी व्यक्ति को, इस उप-धारा के उप-खंड (ए), (बी) या (सी) के अंतर्गत नहीं आने वाली विकलांगता के सभी मामलों में, जैसा कि नियमों में प्रदान किया जा सकता है।

(2) विकलांगता लाभ का भुगतान पैमाने पर और दूसरी अनुसूची में इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जाएगा।

(7) जैसा कि अनुभाग की भाषा से पता चलता है, नियोक्ता का प्रबंधन इस बात पर विचार किए बिना विकलांगता लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या उस विकलांगता के परिणामस्वरूप काम करने या कमाई करने की क्षमता का नुकसान हुआ है। प्रबंधन को विकलांगता के परिणाम के कारण विकलांगता लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी। विकलांगता लाभ के लिए प्रबंधन का दायित्व धारा 51 और विनियमों के अलावा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, यदि कोई हो, तो मैंने विशेष रूप से श्री गर्ग से अधिनियम के किसी भी प्रावधान या किसी भी विनियमन को इंगित करने के लिए कहा है जो मामले में दिखाता है। किसी कर्मचारी की काम करने या कमाने की क्षमता, जो दुर्घटना का शिकार हो गया हो और जो विकलांग हो गया हो, मापनीय रूप से प्रभावित हो, प्रबंधन का दायित्व उस सीमा के अधीन होगा जिस हद तक उसकी काम करने या कमाने की क्षमता क्षीण हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान को इंगित नहीं कर सकते हैं या किसी भी विनियमन का उल्लेख नहीं कर सकते हैं जो यह प्रदान करता है कि धारा 51 के तहत दायित्व ऐसी किसी भी शर्त के अधीन है।

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

(8) रोजगार प्रबंधन को उत्तरदायी बनाने वाली धारा 51 के प्रावधान अनिवार्य हैं। दायित्व केवल इसलिए बनता है क्योंकि विकलांगता हुई है और यह विचार करना कि क्या उस विकलांगता ने कर्मचारी की कामकाजी या कमाई क्षमता को प्रभावित किया है, महत्वहीन हो जाता है।

(9) अधिनियम की धारा 51 के दायरे पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्मचारी की कामकाजी या कमाई क्षमता खराब न होने के कारण विकलांगता लाभ की गणना के लिए औचित्य की कमी की दलील अप्रासंगिक है और सारहीन. ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, यह तर्क कि आवेदक भत्ते का दावा नहीं कर सकता, कोई बल नहीं है।

(10) यह आग्रह किया गया कि ट्रायल कोर्ट इस सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही की गई थी, जिसे दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और परिणामस्वरूप छोटी उंगली का क्षरण हुआ। कर्मचारी मुंशी राम द्वारा, जिसकी दुर्घटना हुई थी, और जिसकी छोटी उंगली कट गई थी, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। 1 जून 1965 को दुर्घटना रिपोर्ट तैयार की गई। यह एक्ज़िबिट पी.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब मुंशी राम. रील वाले धागे को डंप करने जा रहा था। यह कहा गया है कि धारा के तहत. फ़ैक्टरी अधिनियम के 21 के अनुसार, दुर्घटना की घटना से बचने के लिए बंडल प्रेस के चारों ओर बाड़ लगाना प्रबंधन के लिए अनिवार्य था और उस मशीन के चारों ओर कोई बाड़ नहीं होने के कारण पैर फिसलने पर दुर्घटना हो सकती थी।

एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

मोहिंदर कौर बनाम सरदारा सिंह (ढिल्लों, न्यायमूर्ति.)

मुंशी राम का दाहिना हाथ चलती हुई बेट और चरखी के बीच फंस गया था और परिणामस्वरूप छोटी उंगली कट गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस रिपोर्ट और मामले से जुड़े अन्य सबूतों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह एक परिणाम के रूप में हुआ था। यह प्रबंधन की ओर से लापरवाही है कि उसने मुंशी राम के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसकी छोटी उंगली के डर से कोई व्यवस्था नहीं की। वह खोज तथ्य की खोज है। अधिनियम की धारा 82(2) के आधार पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाला गया तथ्य का निष्कर्ष अंतिम है। धारा 82 की उपधारा (2) के अनुसार, कोई भी अपील उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती, इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। इस तथ्य की खोज में कि क्या बाड़ लगाने में प्रबंधन की ओर से लापरवाही हुई थी, इसमें कानून के किसी भी प्रश्न पर विचार शामिल नहीं है, कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना तो दूर की बात है। जिस क्षेत्र में बेल्ट खिसकी थी, उसके चारों ओर बाड़ लगाने की व्यवस्था करने में प्रबंधन की विफलता पर प्रबंधन की ओर से जो निष्कर्ष निकाला गया, वह एक निष्कर्ष है कि प्रबंधन को उनकी ओर से लापरवाही के किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गई है।

ऊपर दर्ज कारणों से. मैं लागत सहित अपील को अस्वीकार करता हूं और निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करता हूं।

बी.एस.जी.



एमएस भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति )

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा